

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,  
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता,  
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,  
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 03 अगस्त, 2010

विषय:- मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में राज्य सरकार की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु अधिवक्तागण का आबद्ध किया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या : 433/XXXVI (1)/2007-75/07 दिनांक 09 अगस्त, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पैरवी/बहस करने हेतु निम्नलिखित अधिवक्तागण को राज्य की ओर से उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर अग्रिम आदेशों तक के लिये तत्काल प्रभाव से आबद्ध करने का निर्णय लिया है :-

क्र.स.	अधिवक्तागण का नाम	पद नाम
1	2	3
1-	श्री सुनील खेड़ा	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
2-	श्री टेक चन्द्र अग्रवाल	अपर शासकीय अधिवक्ता

2- उपर्युक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह एक व्यावसायिक आबन्धन है, किसी 'सिविल पद' पर नियुक्ति नहीं है । इस आबन्धन को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है तथा आबद्ध अधिवक्ता भी इसे कभी भी समाप्त कर सकते हैं । उल्लिखित अधिवक्ता अपनी आबद्धता के दौरान उत्तराखण्ड राज्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के मामले में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की आबद्धता स्वीकार नहीं करेंगे न ही राज्य के विरुद्ध कोई विधिक परामर्श देंगे । आबद्ध अधिवक्ता विधि परामर्शी निदेशिका के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेंगे । सम्बन्धित अधिवक्ता इस आशय का प्रमाण-पत्र भी महाधिवक्ता उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें इन शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है ।

3- उक्त आबद्ध अधिवक्तागण को न्याय विभाग के शासनादेश संख्या 67-XXXVI(1)/2010-43-एक(1) / 2003 दिनांक 25 मार्च, 2010 के अनुसार फीस देय होगी ।

4- कृपया उक्त अधिवक्तागण को तदनुसार सूचित करने तथा आबन्धन हेतु उनकी सहमति प्राप्त कर उन्हें तदनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

भवदीया,

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)  
अपर सचिव ।

संख्या : 159 / XXXVI (1) / 2010-75 / 07भाग-1 तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।

- 2- महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 4- अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
- 6- मुख्य स्थाई अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल ।
- 7- विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ ।
- 8- सम्बन्धित अधिवक्तागण, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल ।
- 9- एन.आई.सी./गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,



( धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी )  
सांयुक्त सचिव ।